महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कार्यकरण का निरीक्षण

30. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के प्रशासनिक कार्यों का संचार मंत्रालय द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता है, जिसके कारण महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में अनेक घपले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) किस प्रकार से इस उपक्रम पर नियंत्रण रखा जाता है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पूंजीकृत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और इसके पास कंपनी के संगम-अनुच्छेदों के अनुसार संगठन के कार्यचालन में कुछ स्तर तक स्वायतता भी है। उपक्रम का प्रशासनिक नियंत्रण एम टी एन एल के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों तथाकथित संगम-अनुच्छेदों के अन्य उपबंधों के तहत संचार मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

एस०टी०डी० नीति के पुनर्निर्धारण में विलम्ब

31. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एस०टी०डी० नीति के पुनर्निर्धारण करने में एक वर्ष से भी अधिक समय लिया जिसके परिणामस्वरूप एस०टी०डी० पी०सी०ओ० नीति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं किया जा सका जब कि आम जनता में इसकी मांग अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में संचार विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों की कोई समीक्षा की है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी, नहीं। एस०टी०डी० पी सी ओ नीति की पुरीक्षा किए जाने तक एस०टी०डी० युक्त सार्वजनिक टेलीफोनों के आबंटन के अस्थायी निलंबन के सिलसिले में मई, 1993 के दौरान अनुदेश जारी किए गए थे। 24.7.93 से संशोधित एस०टी०डी० पी सी ओ नीति को लागू किया गया था।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

देश में नये डाकघरों का खोला जाना

32. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये डाकघरों को खोले जाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस प्रयोजन हेतु निर्धारित लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5350 डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 4305 डाकघर मंजूर किए गए।

(ग) जनवरी, 1984 से पदों के सृजन की प्रक्रिया परिवर्तित हो गई थी तथा ऐसे पदों के सृजन में अंतःमंत्रालयी परामर्श भी शमिल था। परिणामतः सातवीं योजना अवधि के दौरान जितने डाकघर खोले जाने का लक्ष्य था, उतने डाकघर नहीं खोले जा सके।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3600 अतिरिक्त विभागीय तथा 650 विभागीत उप-डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये लक्ष्य डाक सर्किलवार निर्धारित किए जाते हैं न कि राज्यवार, तथापि अधिकांश डाक सर्किलों और राज्यों की भौगोलिक सीमा मूलतः एक (कोटर्मिनत) है। इन लक्ष्यों का सर्किलवार वितरण प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों अर्थात् वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के संबंध में ब्यौरा विवरण में दिया गया है।